

दिनांक

आज्ञा पत्र

20. 3. 2018

अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । ग्राम कीरपुरा की आराजी ख0नं0 289, 303, 304, 306 कुलठकिता-4 रकबा 3.96 हैक्टर में अपीलान्ट का 1/14 हिस्सा एवं ख0नं0 303/1 रकबा 0.02 हैक्टर में 1/28 हि0 है । अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र उक्त आराजी पर मौका कमिश्नर नियुक्त करने का पेशा किया जिस पर अदालत मातहत ने सुनवाई करते हुये स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 22-10-2013 को जारी अन्तरिम अस्थाई निवेधाज्ञा को अमास्त कर दिया । बहस प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त करने पर सुनी गई और उसी प्रार्थना पत्र का आदेश पारित किया किन्तु अन्त में अन्तरिम पारित आदेश को अमास्त करने का आदेश विधि विरुद्ध अमास्त कर दिया । जबकि अप्रार्थी अथवा प्रार्थी की ओर से भी ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेशा नहीं किया गया जिसमें अन्तरिम अस्थाई निवेधाज्ञा के आदेश को अमास्त किया जावे । अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के अन्तरिम आदेश को अमास्त किया है । जिससे विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर आराजी का अन्तरण किया जा सकता है तथा पक्षकारों के मध्य और अधिक मुकदमे बाजी बटने की सम्भावनाएँ अधिक हो गई है । अतः अदालत मातहत मातहत का आदेश दिनांक 13-3-18 को स्थगित किया जाकर दिनांक 22-10-2013 के अन्तरिम आदेश को अपील के निर्णय तक बहाल रखा जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने प्रार्थना





अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अदालत मातहत की आदेशिका के अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश-26 नियम-9सीपीसी की बहस में नियत था। प्रार्थना पत्र में किसी भी पक्षकार के द्वारा भी कोई तथ्य पत्रवली पार नहीं आया जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अन्तरिम आदेश-दिनांक 22-10-2013 को अपास्त किया जावे। अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश पर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश को अपास्त किया है अतः हम यहां पर अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पुनः पारित करें जब तक उभय पक्ष उक्त विवादित आराजी का किसी प्रकार से बैयान/अन्तरण नहीं करें एक दूसरे के कब्जा काशत में कोई दखल अन्दाजी नहीं करें।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप-खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 12-3-2018 एवं 13-3-2018 में दिनांक 22-10-2013 को पारित अन्तरिम आदेश को अपास्त किया है उस हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुन कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित करें तब तक उभय पक्ष विवादित आराजी का बैयान/अन्तरण नहीं करें, एक दूसरे के कब्जा काशत में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होंगे।  
निर्णय सुनाया गया।

श्री-पुष्प अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी